[Shri Arjun Sethi]

giving Rs. 10/- p.m. for per student at a flat rate since 1972-73. The rates prescribed by the Government of India are in existence since 1974-75. The rates have not yet been changed, although the price of essential commodities has gone up considerably with the result the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are experiencing immense financial difficulty for prosecuting their post-matric studies.

The State Government have moved Government of India to increase the rates of post-matric scholarships by Rs. 50/- at a flat rate per month.

Hence in the best interest of the students of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe of the State, I urge upon the Minister of Home Affairs through you, Sir, to accept the proposals of the State Government at the earliest.

(iv) RELIEF MEASURES FOR FLOOD-AFFECTED PEOPLE OF RAJASTHAN

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : राजस्थान के लोगों ने पिछले दिनों भीषण अकाल का सामना जिस धैर्य एवं हिम्मत के साथ किया था इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । परन्तु यहां गत माह 17 से 20 जुलाई के मध्य हुई भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ के कारण राजस्थान के लगभग 1,114 गांव के 67,275 परिवार प्रभावित हुए तथा अतिवृष्टि के कारण 122 लोगों तथा 22,362 पशुओं की मृत्यु एवं 231 व्यक्तियों के लापता होने का भी अनुमान है । कुल मिलाकर लगभग 52,850 घर या तो आंशिक तौर पर अथवा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं । साथ ही यहां पर 15,570 कुंए क्षतिग्रस्त हुए और 300 बिजली तथा डीजल के इंजन पम्प बेकार हुए एवं 41 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बेकार हो गई और 2,77,800 हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसलें नष्ट होने का भी अनुमान लगाया गया है ।

राजस्थान सरकार ने भीषण अकाल का सामना करने के लिए जो काम किया था उसकी प्रगति गत माह आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण चौपट हो गई है । राजस्थान सरकार की अर्थव्यवस्था भी अकाल से निपटने के लिये किये गये व्यय के कारण अस्त व्यस्त हो गई है ।

सर्वप्रथम राजस्थान की जनता की आर्थिक हालत अकाल के कारण अच्छी नहीं थी दूसरे प्रकृति की इस मार ने तो यहां की प्रभावित जनता का मनोबल ही मरोड़ कर रख दिया है । इस समय बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सीमेंट, लोहा इस्पात की चादरें आदि की जरूरत है साथ ही किसानों एवं विस्थापित लोगों को आर्थिक सहायता एवं आवश्यक वस्तुओं के आवंटन की आवश्यकता है । अगर समय रहते यहां की स्थानीय जनता को उक्त सहायता नहीं पहुंचायी गई तो ये लोग पूर्णतः तबाह हो जायेंगे ।

मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे लोगों को वहां के निचले हिस्से में न बसा कर ऊंचाई वाले हिस्सों में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था करावें, ताकि भविष्य में इस प्रकार के खतरों से बचने में सहायता मिल सकें । साथ ही राजस्थान सरकार को इस विपदा से निपटने के लिए मांगी गई धनराशि को अनुदान के रूप में देने की भी व्यवस्था करावे ताकि यहां के पीड़ित परिवारों को पुनः बसाने में समुचित सहायता प्रदान की जा सके ।